(c) राज्य विधानमण्डल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिये जिला स्तर पर, प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा।

(d) अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना का स्वीकृत करने के लिये अधिकृत नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है।

(a) a, b और c (b) b और d दोनों

(c) c और d दोनों (d) a और d दोनों

RPSC School Lecturer-26-04-2017

Ans. (*) : प्रश्नगत दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सत्य नहीं हैं। विकल्प (a) एवं (b) सही है। जबकि विकल्प (c) एवं (d) सही नही है। प्रश्न में उपयुक्त विकल्प का अभाव है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेसा (1996) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों पर एक राज्य के कानून में सामुदायिक संसाधनों के रीति-रिवाजों,धार्मिक प्रथाओं और पांरम्परिक प्रबंधन का ध्यान रखा जाना चाहिए।

218. निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया?

(a) 1996 (b) 1999

(c) 2000 (d) 2011

RPSC College Lecturer 31-10-2018

Ans. (b) : वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम, 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ई. में पारित तथा 23 अप्रैल, 1994 ई. को लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में नये पंचायती राज अधिनियम लागू किए गये।

219. राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के अन्तर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा का विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

(a) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।

(b) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।

(c) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।

(d) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।

RPSC SI 14-09-2021

Ans. (a) : राजस्थान पंचायती राज नियम, 2011 के अंतर्गत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम-से-कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इनमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर। उपनियम (1) के खण्ड (1) में उल्लिखित स्थिति के सिवाय, सचिव सरपंच के साथ परामर्श करने के पश्चात् सात दिन के भीतर बैठक बुलायेगा, और उसकी लोक सूचना नियम तारीख से तीन दिन पूर्व लोक घोषणा और अन्य रीतियों के माध्यम से ग्राम सभा में दी जायेगी। परन्तु यदि सरपंच ऐसा करने में विफल रहता है तो सचिव बैठक बुलायेगा।

220. 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है

(i) अनुसूचित जातियों के लिए

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए

(iii) महिलाओं के लिए

(iv) पिछड़े वर्गों के लिए

सही कूट का चयन कीजिए-

(a) (i) एवं (ii) (b) (i) एवं (iii)

(c) (i),(ii) एवं (iii) (d) (i), (ii), (iii) एवं (ii)

Kanisht Abhiyanta (Civil) 18.05.2022

Ans. (c) : 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों को शक्तियों एवं प्राधिकरणों के विकेन्द्रीकरण का एक बुनियादी ढ़ांचा प्रदान करता है।

221. राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या (1 जनवरी, 2022 को यथाविद्यमान) है-

(a) 30 (b) 34

(c) 35 (d) 36

Kanisht Abhiyanta (Civil) 18.05.2022

Ans. (b) : राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 34 है। नगर निगम की संख्या सात, नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी) 13, नगर पालिका (तृतीय श्रेणी) 58 तथा नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी) 76 हैं इस प्रकार राजस्थान में कुल 188 नगर निकाय है।

222. नगर निगम सभा की अध्यक्षता कौन करता है?

(a) मेयर (b) सभापति

(c) नगर आयुक्त (d) जिला मजिस्ट्रेट

उद्योग प्रसार अधिकारी -2018 (22 जुलाई, 2018)

Ans. (a) – नगर निगम सभा की अध्यक्षता मेयर (महापौर) द्वारा की जाती है। नगर निगम में सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र शामिल होता है महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। भारत में नगर निगम 5 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर/शहर के विकास के लिए एक शहरी स्थानीय निकाय है।

223. निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में,

1. पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल, 1994 को लागू किया गया।
2. ग्रामसभा का वर्ष में दो बार आयोजन अनिवार्य हैं।